A.O.J (S.C)
9.8.18

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(2)न्याय/2016 जयपुर, दिनांक 08-08-2018

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

विषयः-संभाग मुख्यालय अजमेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में एक-एक तथा जयपुर में 3 कॉमर्शियल कोर्ट्स की स्थापना करने बाबत्।
संदर्भः- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08.08.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08.08.2018 के द्वारा Commercial Court, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Act, 2015 and Commercial Court, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Ordinance, 2018 के अन्तर्गत संभाग मुख्यालय अजमेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में एक-एक तथा जयपुर में 3 कॉमर्शियल कोर्ट्स हेतु निम्नानुसार आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने हेतु माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है-

उक्त एक्ट के अन्तर्गत् 7 कॉमर्शियल कोर्ट हेतु निम्नलिखित पद, पद भरे जाने की तिथि से दिनांक 28.02.2019 तक सृजित किये जाते हैं-

क. सं.	नाम पद	Pay Scale/ P.B	G.P.	Matrix-Level	प्रत्येक न्यायालय हेतु पद	कुल पद
1	पीठासीन अधिकारी	51550-63070	-	-	1	7
2	सीनियर मुंसरिम	9300-34800	5400	13	1	7
3	स्टेनोग्राफर ग्रेड-I	9300-34800	4800	12	1	7
4	रीडर ग्रेड-I	9300-34800	4200	11	1	7
5	लिपिक ग्रेड-I	5200-20200	2800	8	1	7
6	लिपिक ग्रेड-II	5200-20200	2400	5	जयपुर हेतु 2-2 तथा अन्य संभाग हेतु 1-1	10
7	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200-20200	1700	1	4	28
8	सूचना सहायक	5200-20200	2800	8	1	7
	कुल					80

इन 7 Commercial Courts हेतु प्रति न्यायालय नवीन आईटम लेखामद 2014-00-105-20-01-05 कार्यालय व्यय (Committed) में उपलब्ध वित्तीय प्रावधान से निम्नानुसार नवीन आईटम कय करने की सहमति प्रदान की जाती है। यदि उक्त लेखामद में प्रावधान पर्याप्त नहीं हो तो विभाग अतिरिक्त प्रावधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कराए।

क. सं.	नवीन आईटम्स	राशि (लाखों में)	कुल वित्तीय भार
1	फर्नीचर	3.00	21.00
2	टेलीफोन(1 कार्यालय एवं 1 निवास हेतु)	0.02	0.14
3	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर (3)	1.80	12.60
4	फोटो स्टेट मशीन	0.75	5.25
	योग	5.57	38.99

उक्त नवीन आईटम्स क्रय करते समय तत्संबंधी नियमों/निर्धारित प्रक्रियाओं एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों की पूर्व पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करावें।

इन 7 Commercial Courts के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु अतिरिक्त बजट प्रावधान की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रावधान के प्रस्ताव पृथक से प्रस्तुत किये जायेंगे।

7 Commercial Courts हेतु उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101804642 दिनांक 07.08.2018 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय
08.8.18
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. वित्त (व्यय-5)/ वित्त (बजट)।
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को 7 Commercial Courts के वेतन भत्तों के भुगतान के संबंध में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बजट प्रावधान के लिये पृथक से प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु।
4. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
5. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक : जी/आई/ए-4(i)(a)104/18/5420-22 दिनांक : 14/8/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर, जोधपुर महानगर, जयपुर महानगर, कोटा एवं उदयपुर ।
02. A.O.J.(Classification) (Website), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / पीठ जयपुर, जयपुर को Upload करने बाबत ।

14.8.18
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

C:\Users\user\Downloads\LETTER 72 (3) ANOOP Mourya.Doc 1009